National AIDS Control Organisation
India's Voice against AIDS
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
www.naco.gov.in

नाको समाचार

जुलाई – सितंबर 2017

खंड X अंक 13

Beti Bachao Beti Padhao

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
Swachh Bharat Abhiyan

Chalo Banaayein Swasth Bharat

AIDS Helpline 1097

अनुक्रमणिका

मुख्य लेख

कार्यक्रम

कार्यक्रम

राज्य

समारोह

मुख्य लेख

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें पूर्वोत्तर और पश्चिमी क्षेत्रीय 6

कार्यक्रम

एन.ए.सी.पी.-IV के अंतर्गत एच.आई.वी. रोकथाम और देखभाल सेवाओं का अवलोकन 8

भारतीय–अफ्रीकी सहयोगः केन्या और रवांडा से प्रतिनिधि–मंडलों का दौरा............ 10

"एन.ए.सी.पी.-IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण" के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला............ 11

आंतरिक सुरक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन............ 13

एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच सेवाओं (एच.सी.टी.एस.), तपेदिक (टी.बी.) और एस.टी.आई. हेतु आई.ई.सी. प्रोटोटाइप की समीक्षा और संवाद कार्यनीतियाँ तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला.... 14

अनाथ और सुग्राही बच्चों (ओ.वी.सी.) की आवश्यकताओं के लिए प्रत्युत्तर अनुक्रिया को बढ़ाना तथा तेज करना – सी.एस.आर. परामर्श कार्यशाला 16

'ब्राउन बैग' सेमिनार – वार्ता माला............ 18

मेट्रो ब्लड बैंक परियोजना का शुभारंभः कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आधुनिकतम रक्ताधान सेवाएं............ 19

राज्य

मुंबई............ 20

पश्चिम बंगाल 20

कर्नाटक............ 21

तेलंगाना............ 21

छतीसगढ़............ 22

समारोह

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस............ 23

संरक्षक की कलम से

मैं नाको समाचार के इस अंक में आप सबका स्वागत करता हूँ!

इस अवसर पर मुझे जुलाई से सितंबर 2017 की तिमाही में नाको और एस.ए.सी.एस. की गतिविधियों के बारे में बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

नाको ने शिलौंग और मुंबई में क्रमशः पूर्वोत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्यों की दो क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का समापन किया। इन क्षेत्रीय बैठकों में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा एड्स नियंत्रण परियोजना के उपयुक्त क्रियान्वयन और निगरानी पर बल दिया गया। पिछले तीन वर्षों में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा प्रगति, समिक्षा तथा चुनौतियों को हल करने और एड्स नियंत्रण परियोजना के लिए नवप्रवर्तनकारी विधि को अपनाने हेतु रूपरेखा पर भी चर्चा की गई।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 सितंबर 2017 को नाको ने आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एस.टी.आई./एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़ी संख्या तक पहुँचना है।

सरकार द्वारा "जाँच और उपचार" कार्यनीति पहले ही लाँच की जा चुकी है, इसलिए बाकी बचे पी.एल.एच.आई.वी. को प्रोत्साहित करना और उन्हें मुफ्त ए.आर.टी. सेवाओं की परिधि के अंतर्गत लाना केन्द्र और राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

इन शब्दों के साथ, मैं समाचार पत्र की टीम, पाठकगण, और सभी भागीदारों का आभार व्यक्त करता हूँ।

सर्वश्रेष्ठ शुभकामनाओं के साथ!

श्री संजीव कुमार
अपर सचिव और महानिदेशक, नाको,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

संयुक्त सचिव की कलम से

प्रिय पाठकगण,

मुझे नाको समाचार में पहली बार अपनी राय और विचार साझा करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है!

आप में से अधिकांश लोगों को विदित होगा कि वर्तमान वित्त वर्ष 2017–18 में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को दूसरी किस्त पहले ही रिलीज की जा चुकी है। अब निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यक्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कमर कसने का समय आ गया है। यहाँ, मैं आगे की किस्तों को रिलीज करना जारी रखने के लिए सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों में पी.एफ.एम.एस. के व्यय/अग्रिम/अंतरण (ई.ए.टी.) मॉड्यूल को पूर्णतया प्रचालित करने पर बल देना चाहूँगा। मुझे आशा है कि सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियाँ ई.ए.टी. मॉड्यूल को प्रचालित करने के लिए निर्धारित समय–सीमा का पालन करेंगी।

वर्तमान संस्करण में, आपको कारागारों में एच.आई.वी. रोकथाम एवं उपचार सेवा; लक्षित हस्तक्षेप (टी.आई.) विधि और गृह मंत्रालय के साथ गहन समन्वय से नाको द्वारा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे अन्य पहुँच मॉडलों का एक विश्लेषण देखने को मिलेगा।

मेट्रो ब्लड बैंक के संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के क्रम में, 10 जुलाई 2017 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसने पश्चिम बंगाल की जमीन पर, जो राज्य द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, केन्द्र की स्थापना और संचालन करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता को औपचारिक रूप प्रदान किया।

इस संस्करण में विभिन्न राज्य स्तरीय समारोहों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस (आई.वाई.डी.) मनाने के लिए सप्ताह–कालिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। यह अत्यधिक प्रशंसनीय है कि राज्यों में पूरे उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया जिसमें सांस्कृतिक समारोहों से लेकर बाहय समारोह शामिल थे।

मैं आप सभी पाठकगण, अंशदाताओं और संपादकीय टीम की सतत सहायता के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ।

कृपया अपने विचार एवं सुझाव हमें भेजें ।

शुभकामनाएं !

श्री आलोक सक्सेना
संयुक्त सचिव, नाको
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

संपादक की कलम से

90:90:90 हम कहाँ पर हैं ?

आजकल हर कोई 2020 तक 90:90:90 के बारे में चर्चा कर रहा है। आइये, हम आत्मविश्लेषण करते हैं कि उनके संबंध में हम कहाँ पर हैं और पूर्वकथित तुरंत कार्रवाई लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या और करना अपेक्षित है।

पहला 90, अर्थात 90% अनुमानित पी.एल.एच.आई.वी. को अपनी वस्तुस्थिति ज्ञात है – प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस मोर्चे पर उपलब्धि लगभग 75% है। अनुमानित पी.एल.एच.आई.वी. का 90% लगभग 19 लाख बनता है और यह अत्यधिक संभव प्रतीत हो रहा है कि गर्भवती महिलाओं और सामान्य क्लायंटों की बढ़ रही जांच के अलावा समुदाय आधारित जांच को अंगीकार किए जाने और शुरु की जा रही स्वतः जांच पहलकदमियों के साथ, भारत अगले 3 वर्ष में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लेगा। प्रत्येक वर्ष एच.आई.वी. के लिए जाँच किए जा रहे 3.5 करोड़ लोगों में से लगभग 2 लाख लोग पॉजीटिव पाए जा रहे हैं।

दूसरा 90, अर्थात जो लोग अपनी वस्तुस्थिति जानते हैं उनमें से 90% को ए.आर.टी. पर लाना – यह वास्तव में 'सभी का उपचार' की नीति के बावजूद एक चुनौती बन रहा है क्योंकि वहाँ एल.एफ.यू. की एक बड़ी सूची मौजूद है और उनका पता लगाना एक ऐसी कवायद है जिसके लिए सभी भागीदारों के विशालकाय प्रयास की आवश्यकता है। लगभग 11.5 लाख पी.एल.एच.आई.वी. उपचार पर हैं और 2020 तक यह संख्या 17 लाख हो जानी चाहिए। उन सब को, जो प्री–ए.आर.टी. पर हैं, लगातार ए.आर.टी. पर लाया जा रहा है, फिर भी इस कवायद को पूरा करने में 9–10 महीने और लग सकते हैं। ए.आर.टी. लाभार्थियों की सूची में हर महीने 22000 से अधिक व्यक्ति जोड़े जा रहे हैं और इस गति के साथ अगले 2 वर्ष में हम कह सकते हैं कि वहां लगभग 15 लाख व्यक्ति हो जाएंगे। शायद थोड़ा सा अतिरिक्त कठोर प्रयत्न हमें वांछित लक्ष्य पर पहुंचा देगा।

तीसरा 90, अर्थात जो लोग ए.आर.टी. पर हैं उनमें से 90% का वायरल लोड संदमित है – इस सूचक के दो प्रयोजन हैं; पहला, यह एक प्रतिनिधि सूचक है जिससे पता चलता है कि ए.आर.टी. ले रहे लोगों में से कितनों को रोककर रखा जा रहा है और दूसरा, नियमित निगरानी के साथ प्रथम पंक्ति पर विफलता का जल्दी पता चल पाएगा। नियमित रूप से वायरल लोड जांच द्वारा निगरानी अभी शुरु होनी है लेकिन विभिन्न मोर्चों पर प्रगति के साथ यह अगले वर्ष की पहली तिमाही में आरंभ की जा सकती है और एक बार इसके आरंभ हो जाने के बाद इसकी व्यापकता को तेजी से बढ़ाया जाएगा क्योंकि नाको 3 मोर्चों पर कार्यरत है, अर्थात (i) जाँच का कार्य बाहरी निजी एजेंसी को सौंपना – संविदा दिए जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, (ii) 80 वायरल लोड मशीनें खरीदकर जन स्वास्थ्य अवंसरचना का सुदृढ़ीकरण – मार्च 2018 तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है। (iii) जीनक्सपर्ट मशीनों की अतिरिक्त क्षमता को इस्तेमाल करना – व्यावहारिक तौर पर पूर्वोत्तर और सुदूर क्षेत्रों के लिए यह प्रक्रिया भी अगले वर्ष की पहली तिमाही में आरंभ हो सकती है।

सारकथन के रूप में, हम व्यवस्थाओं को उनके स्थान पर पहले ही तैनात कर चुके हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत 2020 तक 90:90:90 के इन तुरंत कारवाई लक्ष्यों को हासिल कर लेगा।

आइये, पथ पर बने रहने के लिए हम सब साथ मिलकर अतिरिक्त कठोर प्रयत्न करें।

जय हिंद!

डॉ. नरेश गोयल
डी.डी.जी. (एल.एस. एंड आई.ई.सी.),
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

मुख्य लेख

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें – पूर्वोत्तर और पश्चिमी क्षेत्र

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना की प्रगति की वस्तुस्थिति की समीक्षा और मूल्यांकन करने के अनुसरण में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने शिलौंग, मेघालय और मुंबई में क्रमशः पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों का लक्ष्य पिछले तीन वर्ष में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना, चुनौतियों की जांच करके सूची बनाना और एड्स नियंत्रण परियोजना की कार्यसाधकता में सुधार लाने के लिए नवप्रवर्तनका. री विधियों की रूपरेखा उपलब्ध कराना था।

23 से 25 अगस्त 2017 को सी.डी.सी. और एफ.एच.आई. 360 की भागीदारी के साथ पहली क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको द्वारा की गई। श्री पी.डब्ल्यू. इंगती, अपर प्रमुख सचिव, मेघालय सरकार, श्री एच.एम. शांगप्लीआंग, सचिव और एम.डी. (एन.एच.एम.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार भी बैठक में उपस्थित थे। समस्त 8 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के परियोजना निदेशकों (पी.डी.) (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागलैंड, सिक्किम और त्रिपुरा), स्वास्थ्य विभागों, असम राइफल्स, कारागार विभाग, सी.डी.सी., एफ.एच.आई. 360 के प्रतिनिधियों, सामुदायिक प्रतिनिधियों, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों और नाको के अधिकारियों ने इस 3 दिवसीय बैठक में भाग लिया। एन.ए.सी.पी. के प्रत्येक संघटक (टी.आई., निगरानी एवं मूल्यांकन, डी.ए.पी.सी.यू., एस.टी.आई., परामर्श सहित आधार सेवाएं, जांच, एच.आई.वी.–टी.बी., एच.आई.वी. के एम.टी.सी.टी. और उपदंश का उन्मूलन, प्रचालनिक अनुसंधान, आई.ई.सी. एंड मेनस्ट्रीमिंग और प्रयोगशाला सेवाएं) में की गई प्रगति की सतर्कतापूर्वक समीक्षा की गई। सी.डी.सी. द्वारा एफ.एच.आई. 360 के माध्यम से सहायता–प्राप्त परियोजना 'सनराइज' की भी समीक्षा की गई। बैठक में उन प्रमुख क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया जिनमें कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में जानपदिक रोग विज्ञान तथ्य–पत्रः खंड 1 और ब्लड बैंकों की मूल्यांकन रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया।

बैठक के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में जानपदिक रोग विज्ञान तथ्य–पत्रः खंड 1 और ब्लड बैंकों के मूल्यांकन का विमोचन

शिलौंग, मेघालय में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक – पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरान प्रतिभागी

12 से 14 सितंबर 2017 को मुंबई में यू.एस.एड और एफ.एच.आई. 360 की भागीदारी में पश्चिमी क्षेत्र के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको ने बैठक की अध्यक्षता की। सात राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों/जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी से परियोजना निदेशकों (दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई और राजस्थान), स्वास्थ्य विभाग, डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एस.एड, यू.एन.एड्स, सी.डी.सी., एफ.एच.आई. 360 के प्रतिनिधियों, सामुदायिक प्रतिनिधियों, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों और नाको के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

मुंबई में पश्चिमी राज्यों के संबंध में जानपदिक रोग विज्ञान तथ्य–पत्रः खंड II और ब्लड बैंकों की मूल्यांकन रिपोर्ट का विमोचन

बैठक में संयुक्त सचिव, नाको द्वारा परियोजना के सभी पहलुओं के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा की गई। इसके दौरान 'लिंकेज परियोजना' और 'समूह जिला परियोजनाओं' की भी समीक्षा की गई। व्यावसायिक परिसंघों, जैसे आई.एम.ए., एफ.ओ.जी.एस.आई., समाज शास्त्र और चिकित्सा के शैक्षणिक संस्थानों आदि की उपस्थिति बैठक की मुख्य विशेषता थी। बैठक के दौरान पश्चिमी राज्यों के संबंध में जानपदिक रोग विज्ञान तथ्य–पत्रः खंड II और ब्लड बैंकों की मूल्यांकन रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया।

मुंबई में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक – पश्चिमी क्षेत्र के दौरान प्रतिभागी

टी.आई. डिवीजन एवं टीम, नाको

कार्यक्रम

एन.ए.सी.पी.–IV के अंतर्गत एच.आई.वी. रोकथाम और देखभाल सेवाओं का अवलोकन

दीर्घावधि विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) - 3 का 2030 तक एड्स का उन्मूलन करने का एक समर्पित लक्ष्य है। ड्रग इस्तेमाल करने वाले लोगों और कारागार में लोगों के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सिफारिशें की गई हैं। एस.डी.जी. - 3 में 2020 तक मुख्य आबादियों, ड्रग इस्तेमाल करने वाले लोगों और कारागार में मौजूद लोगों के बीच नए एच.आई.वी. संक्रमणों का 75% न्यूनीकरण करने का आह्वान भी किया गया है। कैदियों के उपचार हेतु संशोधित संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों (2015 में अनुमोदित) के खंड 22 कैदियों के लिए रोकथाम और एंटीरेट्रोवायरल उपचार सहित एच.आई.वी. सेवा उपलब्ध कराने की सिफारिश करता है।

अक्टूबर 2014 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य मुख्य हितधारकों के साथ आयोजित की गई राष्ट्रीय परामर्श बैठक ने राष्ट्रीय कारागार एच.आई.वी. हस्तक्षेप कार्यनीति को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त किया था। देश में कारागार एच.आई.वी. हस्तक्षेप प्रारंभ किए जाने के एक अग्रदूत के रूप में, नाको ने क्षेत्रीय संवेदीकरण कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन किया था और एक योजनाबद्ध आधार पर हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करने की योजना भी बनाई थी।

व्यापक पैकेज से मुख्य एच.आई.वी. हस्तक्षेपः

1. सूचना, शिक्षा और संवाद (आई.ई.सी.)
2. एच.आई.वी. जांच और परामर्श
3. एच.आई.वी. उपचार, देखभाल और सहायता
4. तपेदिक की रोकथाम, निदान और उपचार
5. एच.आई.वी. के माँ–से–बच्चे को संचारण की रोकथाम
6. यौन संचारित संक्रमणों की रोकथाम और उपचार
7. ओपीऑयड प्रतिस्थापन उपचार सहित ड्रग निर्भरता उपचार
8. विषाणुजनित यकृतशोथ के निदान और उपचार हेतु रेफरल
9. चिकित्सा या दंत सेवाओं के माध्यम से एच.आई.वी. संचारण के बारे में जागरुकता बढ़ाना
10. गोदना, छेदन और त्वचा छेदन के अन्य रूपों के माध्यम से एच.आई.वी. संचारण के बारे में जागरुकता बढ़ाना

फेज–1 एच.आई.वी. हस्तक्षेप का लोकार्पणः 6 फरवरी 2016 को इम्फाल, मणिपुर में माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा 'सनराइज परियोजना' (पूर्वोत्तर राज्यों में आई.डी.यू. के लिए एच.आई.वी. रोकथाम एवं देखभाल का संवर्धन करने के लिए एफ.एच.आई. 360 के माध्यम सी.डी.सी. द्वारा सनराइज परियोजना की सहायता की जा रही है) के भाग के रूप में एच.आई.वी. हस्तक्षेप का लोकार्पण किया गया था।

8 जुलाई 2016 को चंडीगढ़ में अपर सचिव और महानिदेशक, नाको के मार्गदर्शन के अंतर्गत, (ईमैनुअल हॉस्पीटल एसोसिएशन द्वारा एड्स फोन्ड्स, नैदरलैंड की वित्तीय सहायता के साथ पंजाब और चंडीगढ़ में कारागार एच.आई.वी. हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है) नाको ने पंजाब और चंडीगढ़ में फेज–1 एच.आई.वी. हस्तक्षेप प्रारंभ किया था।

7 राज्यों में 15 कारागारों (पंजाब और चंडीगढ़ में 10 केन्द्रीय कारागारः अमृतसर, लुधियाना, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, पटियाला, बठिंडा, चंडीगढ़) और पूर्वोत्तर राज्यों से 5 केन्द्रीय कारागरें: इम्फाल, एजवाल, दीमापुर, शिलौंग और गुवाहाटी) में क्रियान्वयन के पिछले 12 महीनों में हासिल हुए परिणामों ने देश में अन्य कारागारों में हस्तक्षेपों का विस्तार किए जाने का सुदृढ़ साक्ष्य उपलब्ध कराया है। जुलाई 2017 की स्थिति के अनुसार, एच.आई.वी. के लिए जांच किए गए 35691 कैदियों में से 922 कैदियों को एच.आई.वी. पॉजीटिव पाया गया था, 603 कैदियों को पहले ही ए.आर.टी. सेवाओं के साथ लिंक किया जा चुका है (पंजाब में 2.4% पॉजीटिविटी)।

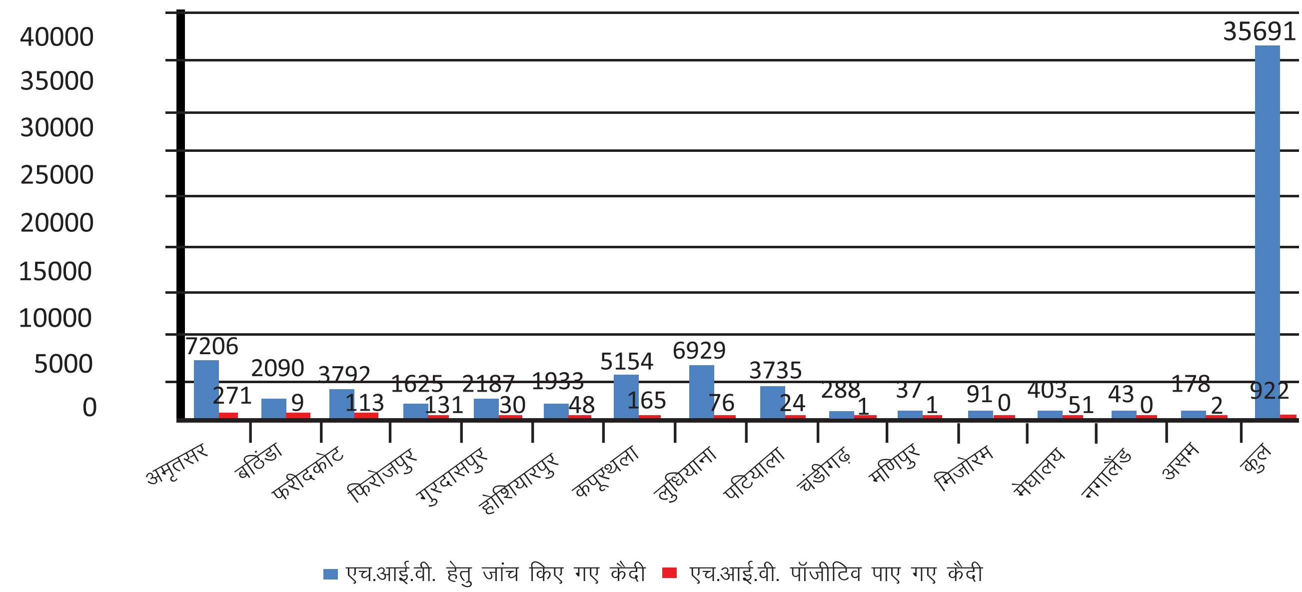

पूर्वोत्तर राज्यों से रिपोर्ट किए अधिकांश पॉजीटिव मामले मेघालय से थे, अर्थात समग्र रूप से 13282 कैदियों में से 31.9% एच.सी.वी. से संक्रमित थे, जिनमें से 869 कैदियों का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं के साथ यकृत शोथ–सी के लिए उपचार किया गया था (पूर्वोत्तर में 18.3% यकृत शोथ–सी पॉजीटिविटी दर्ज की गई थी)। जिन 120 कैदियों का तपेदिक का निदान हुआ था, उनमें से 110 कैदियों को तपेदिक उपचार के साथ लिंक किया गया था। इस प्रतिवेदन अवधि के दौरान, 90 कैदियों का यौन संचारित संक्रमणों के लिए उपचार किया गया था।

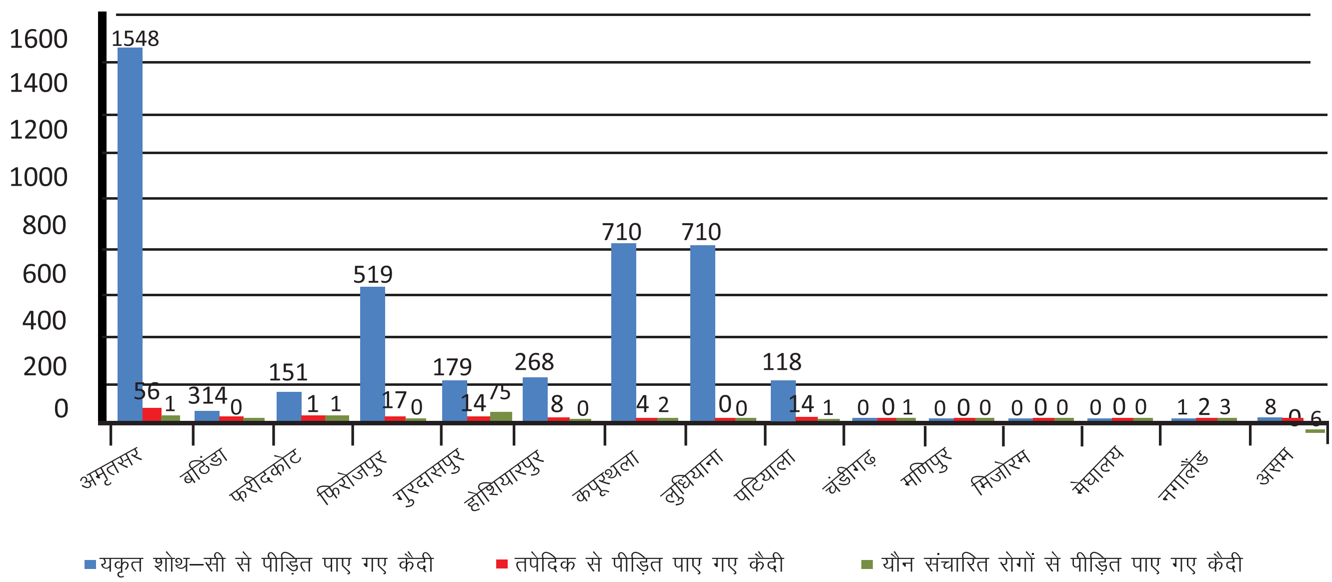

फेज–II एवं III कारागार एच.आई.वी. हस्तक्षेप: हाल ही में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए कारागार एच.आई.वी. हस्तक्षेप संयुक्त कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों और राज्य कारागार विभागों के बीच राज्य स्तरीय अंतर–विभागीय बैठकों का आयोजन किया गया था। इस समय ये राज्य लगभग 98300 कैदियों को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 67 कारागार स्थलों पर फेज–II कारागार एच.आई.वी. हस्तक्षेपों का संचालन कर रहे हैं। दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा तिहाड़ ज़ेल में ओ.एस.टी. सेवाओं को क्रियान्वित किए जाने सहित चालू एच.आई.वी. हस्तक्षेपों को औपचारिक रूप देने के लिए यह प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ भी फेज–III कारागार हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं।

आगे का मार्गः

- भारतीय कारागार के आंकड़ों (2015) का विश्लेषण दर्शाता है कि वहां 1,401 कारागारों में कुल 4,19,623 कैदी थे जिनमें 2,82,076 मुलाजिम (कुल कैदियों का 67.2%) थे। 88% मुलाजिमों की आयु 50 वर्ष से कम थी और अंततः कारागार से बाहर समुदाय में वापस लौट जाएंगे।
- कारागारों में एच.आई.वी. के फैलाव के विशालकाय जन स्वास्थ्य फलितार्थ हैं क्योंकि लगभग सभी कैदी अपने समुदाय में वापस लौटेंगे और सामान्य आबादी के बीच एच.आई.वी. संक्रमण फैलाने की संभावना रखते हैं।
- कारागारों में एक वृहत् एच.आई.वी. रोकथाम एवं उपचार सेवा के साथ इस संकटमय मसले का निवारण करने के उद्देश्य से, वर्तमान में नाको द्वारा गृह मंत्रालय के गहन समन्वय के साथ संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के माध्यम से टी.आई. विधि और अन्य पहुँच मॉडलों को प्रयोग में लाया गया है।
- हाल ही (जून 2017) में अनुमोदित "एक एड्स मुक्त भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करना" नामक एच.आई.वी./एड्स और एस.टी.आई. हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति योजना (2017–2024) में एन.ए.सी.पी.–IV के अंतर्गत कारागार एच.आई.वी. संघटक को शामिल किया गया है जो 2030 तक एड्स महामारी का उन्मूलन करने की दिशा में अग्रसर होने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री अब्राहम लिंकन, तकनीकी विशेषज्ञ–क्षति न्यूनीकरण
सुश्री सोफिया खुमुकशाम, परियोजना अधिकारी–आई.डी.यू.
सुश्री किम हौजेल, तकनीकी अधिकारी–आई.डी.यू.
श्री शिन सामटे, तकनीकी अधिकारी–आई.डी.यू.

भारतीय–अफ्रीकी सहयोगः केन्या और रवांडा से प्रतिनिधि–मंडलों का दौरा

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको, केन्या के प्रतिनिधि–मंडल के साथ संवाद करते हुए

भारत–अफ्रीका संचालित दक्षिण–दक्षिण सहयोग का एक मुख्य फोकस क्षेत्र भारतीय और अफ्रीकी रोग–नैदानिक अनुसंधान केन्द्रों (सी.आर.सी.), मुख्य आबादी समुदायों और क्षेत्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों एवं सगंठनों के बीच एक उपयुक्त सहायता संघ का सृजन करना है। इस पहलकदमी को आगे बढ़ाते हुए, 24–28 जुलाई 2017 को नौ सदस्यों के एक दल ने भारत का दौरा किया, जिसमें केन्या और रवांडा से सामुदायिक प्रतिनिधि और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन ईनीशिएटिव (आई.ए.वी.आई.) के अधिकारी शामिल थे।

इस दौरे का मुख्य उद्देश्य एच.आई.वी. का जल्दी पता लगाने और सोशल मीडिया की प्रणबद्धता पर फोकस के साथ भारतीय और अफ्रीकी प्रमुख आबादियों (मुख्य तौर पर जी.बी.एम.एस.एम.) के बीच एक संयुक्त जनसंख्या आधारित सामुदायिक प्रणबद्धता अध्ययन प्रोटोकॉल तैयार करने की दिशा में कार्य करना था। प्रतिनिधि–मंडलों के दौरे का प्रायोजन इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन ईनीशिएटिव द्वारा किया गया था।

27 जुलाई 2017 को प्रतिनिधि–मंडलों ने संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए नाको का दौरा किया। बैठक में, राष्ट्रीय प्रत्युत्तर के संबंध में एक व्यापक प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया और नाको के अधिकारीगण ने विभिन्न संघटकों के बारे में भारत के अनुभवों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा किया। प्रतिनिधि–मंडलों को उनके संबंधित देशों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न प्रकार की हस्तक्षेपों का भी उदाहरण दिया गया। टीम ने अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको से भी मुलाकात की, और भारतीय–अफ्रीकी सहयोग के विभिन्न घटकों पर चर्चा की। उनके दौरे के भाग के रूप में, टीम ने मुम्बई जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी, मुंबई में एकता फाउंडेशन और हमसफर ट्रस्ट के टी.आई. स्थलों तथा नई दिल्ली में एस.पी.ए.सी.ई., एम.एस.एम. और टी.जी. हस्तक्षेप और वाई.आर.जी. केयर स्थलों का भी दौरा किया।

सुश्री विनिता वर्मा,
परामर्शदाता (मूल्यांकन एवं ओ.आर.), अनुसंधान, नाको

कोलकाता में 'एन.ए.सी.पी.–IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान गणमान्य व्यक्ति

"एन.ए.सी.पी.–IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण" के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति के बीच एच.आई.वी. और एड्स की रोकथाम का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से, एच.आई.वी. के प्रतिकार्य संसार का प्रत्युत्तर एन.ए.सी.पी.–IV की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। 16–17 फरवरी 2017 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के सहयोग से नाको द्वारा 'कार्य संसार और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में एक राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

11 एवं 12 जुलाई 2017 को कोलकाता में आई.एल.ओ. और डब्ल्यू.बी.एस.ए.पी. एंड सी.एस. के सहयोग से नाको द्वारा 'एन.ए.सी.पी.–IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में एक दो–दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योगों द्वारा एच.आई.वी./एड्स परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में अच्छी पद्धतियों की साझेदारी, विभिन्न व्यवसायों में एच.आई.वी. पॉजीटिविटी को दर्शाने वाले आई.सी.टी.सी. के आंकड़ों के विश्लेषण के संबंध में राज्य निर्दिष्ट प्रस्तुतीकरण, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत कामगारों तक पहुंचने का अनुभव, कार्यस्थल पर पी.एल.एच.आई.वी. के विरुद्ध कलंक और भेदभाव का न्यूनीकरण इस कार्यशाला की विशिष्टताएं थीं। नाको और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के दल ने एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के संबंध में कोल इंडिया और उसकी नौ सहायक इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को समझने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के प्रधान कार्यालय का दौरा किया।

भोपाल में 'एन.ए.सी.पी.–IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान गणमान्य व्यक्ति

21 और 22 जुलाई 2017 को भोपाल में आई.एल.ओ. और मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के सहयोग से नाको द्वारा एन.ए.सी.पी.–IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में एक अन्य दो–दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नाको और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के दल ने कार्यस्थल हस्तक्षेप और युवाओं एवं नजदीकी समुदायों को जागरूक करने के संबंध में की गई पहल को समझने के लिए अनंत स्पिनिंग मिल का दौरा किया।

गोवा में 'एन.ए.सी.पी.–IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान गणमान्य व्यक्ति

इसी क्रम में, 6 एवं 7 सितंबर को पंजिम, गोवा में आई.एल.ओ. और गोवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के सहयोग से नाको द्वारा 'एन.ए.सी.पी.–IV में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों, नियोक्ता संगठनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियनों, पॉजीटिव लोगों के नेटवर्कों, नागरिक समाज संस्थाओं और आई.एल.ओ., नाको एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के अधिकारियों ने भाग लिया। नाको और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के दल ने कार्यस्थल और नजदीकी समुदायों में प्रारंभ की गई गतिविधियों को समझने के लिए मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया। वरिष्ठ प्रबंधक–वर्ग, चिकित्सा दल और एच.आई.वी./एड्स रोकथाम की गतिविधियों में व्यस्त संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई।

प्रमुख परिणाम और आगे का मार्ग - दर्शन

- कोलकाता, भोपाल और गोवा में आयोजित तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं में एच.आई.वी. के प्रति कार्य संसार के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों, नियोक्ता संगठनों जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज संस्थाओं को एकजुट किया गया।
- निर्माण, कृषि, परिवहन आदि जैसे विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत कामगारों के बीच एच.आई.वी. पॉजीटिविटी को समझने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के आई.सी.टी.सी. आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी ने औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के बीच एच.आई.वी. रोकथाम योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हितधारकों जैसे उद्योगों, नियोक्ता संगठनों आदि को संबोधित करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार कीं।
- एच.आई.वी. के प्रति कार्य संसार के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण करने हेतु राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गईं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड (कोयला), मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (जहाजरानी), गोवा शिपयार्ड (रक्षा) ने एच.आई.वी./एड्स संबंधी हस्तक्षेपों को सुदृढ़ीकरण करने की प्रतिबद्धता दर्शायी है।
- कामगारों हेतु स्वैच्छिक परामर्श और जांच (VCT work)को प्राथमिकता दी जाएगी और उपलब्ध सेवाओं के साथ लिंकेज का संवर्धन किया जाएगा।
- राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा, जिन्होंने तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भाग लिया था, राज्य स्तरीय परामर्शों का आयोजन किया जाएगा।

श्री अशीष वर्मा
आई.ई.सी. एंड एम.एस.,नाको

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको और डॉ. मुकेश सक्सेना, ए.डी.जी. (चिकित्सा) सी.ए.पी.एफ., एन.एस.जी एवं ए.आर., आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

आंतरिक सुरक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन

एच.आई.वी. के प्रति बहुक्षेत्रक प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण करने के लिए अंतर–मंत्रालय सहयोग का संवर्धन करने हेतु मुख्य धारा में लाना और भागीदारी करना कार्यनीतिपरक विधियों में से एक है। अंतर–मंत्रालय सहयोग को 'एकीकृत प्रत्युत्तरों' का निर्माण करने की दिशा में अत्यधिक महत्व की एक पहल के रूप में देखा जाता है, जो एच.आई.वी. संक्रमण के प्रति सुग्राहिता पर कार्रवाई करने और प्रभावित समुदायों पर इस बीमारी के बोझ का प्रशमन करने का एक कारगर तरीका साबित हुआ है। इस सबंध में, सुग्राहिता न्यूनीकरण, सेवाओं के एकीकरण और पी.एल.एच.आई.वी. हेतु सामाजिक सुरक्षा के लिए पहुँच का संवर्धन करने के उद्देश्य से, नाको ने भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के साथ भागीदारी का प्रस्ताव किया है। नाको ने समझौता ज्ञापन करके मुख्य मंत्रालयों के साथ भागीदारी को औपचारिक रूप प्रदान किया है।

अंतर–मंत्रालय सहयोग का सुदृढ़ीकरण करने हेतु इसके प्रयास के अंतर्ग्रत 1 सितंबर 2017 को सम्मेलन हाल, नाको में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और आंतरिक सुरक्षा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और डॉ. मुकेश सक्सेना, अपर महानिदेशक (चिकित्सा), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एवं ए.आर., आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसर पर गृह मंत्रालय और नाको के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

उद्देश्य:

- एस.टी.आई./एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जानकारी के साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़ी संख्या तक पहुँचना
- पी.एल.एच.आई.वी. और एम.ए.आर.पी. के विरुद्ध कलंक और भेदभाव का न्यूनीकरण करने के लिए पुलिस बलों के बीच मानव परिप्रेक्ष्य और उपयुक्त कौशलों का निर्माण करने में सहायता करना।
- आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में एस.टी.आई./एच.आई.वी./एड्स सेवाओं का एकीकरण करना
- आंतरिक सुरक्षा विभाग की परिधि के अधीन सभी बलों को प्रशिक्षण में एच.आई.वी./एड्स को शामिल करने का निर्देश देना

श्री अशीष वर्मा
आई.ई.सी. एंड एम.एस., नाको

एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच सेवाओं (एच.सी.टी.एस.), तपेदिक (टी.बी.) और एस.टी.आई. हेतु आई.ई.सी. प्रोटोटाइप की समीक्षा और संवाद कार्यनीतियाँ तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला

मौजूदा आई.ई.सी. प्रोटोटाइप की समीक्षा और संवाद कार्यनीति तैयार करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला

2030 तक जन स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स का उन्मूलन करने के पथ पर, भारत 2020 तक वैश्विक 90:90:90 लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा है। एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच सेवाओं (एच.सी.टी.एस.) को बढ़ाना प्रथम 90 को हासिल करने की दिशा में अत्यावश्यक है, जिसके तहत देश में अनुमानित पी.एल.एच.आई.वी. में से 90% को अपनी एच.आई.वी. वस्तुस्थिति ज्ञात हो। इसके लिए, नाको ने नया "राष्ट्रीय एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच सेवाएं (एच.सी.टी.एस.) दिशानिर्देश, 2016" तैयार किया है।

जागरुकता का प्रसार करने और लक्षित समूहों के बीच व्यवहारवादी बदलाव लाने और सेवा प्रदाताओं के लिए आधार सेवा डिवीजन (बी.एस.डी.) हेतु आई.ई.सी. सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से, 2 एवं 3 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में प्लान इंडिया के सहयोग से मौजूदा आई.ई.सी. प्रोटोटाइप की समीक्षा और एच.सी.टी.एस. एवं एस.टी.आई. हेतु संवाद कार्यनीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौजूदा आई.ई.सी. सामग्री की व्यापक समीक्षा ने मौजूदा सामग्री के अंगीकरण और नई सामग्री के विकास हेतु मार्गदर्शन करने के लिए मौजूदा सामग्री में अंतरालों और सामने मौजूद चुनौतियों की पहचान करने में सहायता की।

इस बैठक में आई.ई.सी. और बी.एस.डी. से राज्य प्रतिनिधियों, सभी विकास भागीदारों अर्थात डब्ल्यू.एच.ओ., यूनीसेफ, सी.डी.सी., सी.एच.ए.आई., यू.एस.एड, यू.एन.एड्स, प्लान इंडिया, साथी के प्रतिनिधियों तथा नाको के अधिकारियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला सामूहिक कार्य की दिशा में अग्रसर हुई। लगभग 15–18 प्रतिभागियों वाले चार समूहों का गठन किया गया और प्रत्येक समूह ने वर्तमान परिस्थिति, अंतरालों और आई.ई.सी. की आवश्यकता की गहराई से जांच करने के लिए बी.एस.डी. के एक संघटक को लिया। चार समूहों को एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.), अभिभावक से शिशु को संचारण की रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी.), यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) और एच.आई.वी. एवं तपेदिक सह–संक्रमण के विषय सौंपे गए। सामूहिक कार्य के बुनियादी उद्देश्य थेः 1) मौजूदा सामग्री की समीक्षा करना, 2) अंतरालों और चुनौतियों की पहचान करना, 3) अंगीकरण हेतु मौजूदा सामग्री, 4) थीम पर अपेक्षित नई सामग्री, 5) मुख्य संदेशों के साथ कार्यनीति और 6) नवप्रवर्तन।

कार्यशाला में निम्नलिखित संस्तुति की गईं:

समूह 1 – आई.सी.टी.सी.

समूह 1 मुख्य आबादियों, विशेषकर प्रजनन आयु की किशोर लड़कियों के लिए लक्षित आई.ई.सी. सामग्री तैयार की जानी चाहिए और डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल, उदाहरणार्थ ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से संदेश, डेटिंग साइट्स (टिंडर) पर विज्ञापनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मीडिया सामग्री के इस्तेमाल के संबंध में कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु आईसीटीसी टूलकिट तैयार किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

समूह 2 – पी.पी.टी.सी.टी.

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सिफारिशें:

समूह 2 ने राजनैतिक इच्छा पैदा करने हेतु पक्षसमर्थन और डिजिटल और मास मीडिया के माध्यम से एक ब्राण्ड अम्बेसडर के प्रसार करने की सिफारिश की। इसने प्रसव कक्ष की परिचारिकाओं के लिए मानक कार्यपद्धति के प्रसार और प्रदाताओं एवं लाभार्थियों हेतु प्रोत्सा. हन की सिफारिश भी की थी।

निजी क्षेत्र के लिए सिफारिशें:

सुरक्षित यौन पद्धतियों, एच.आई.वी. और उपदंश जांच तक पहुँच, और गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवारों के लिए जीवनसाथी की जांच के संबंध में सामग्रियां तैयार करने और राष्ट्र स्तरीय परियोजनाओं, परामर्श सेवाओं एवं एच.सी.पी. हेतु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में जागरुकता पैदा करने का सुझाव दिया गया था।

समूह 3 – एस.टी.आई.

समूह 3 ने लक्षित संदेश देने, उदाहरणार्थ पराचिकित्सा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में एस.टी.आई. का एकीकरण और अंतर–विभागीय सहयोग, उदाहरणार्थ किशोरावस्था हितैषी स्वास्थ्य क्लीनिकों (आर.के.एस.के.) में एस.टी.आई. के संबंध में सत्र लेने के लिए एन.एच.एम. (आर.के.एस.के.) और आई.सी.टी.सी./एस.टी.आई. परामर्शदाताओं के साथ, की सिफारिश की थी। हेल्पलाइन सेवाएं प्रारंभ करने और सेवाओं की एक डायरेक्टरी बनाए जाने का भी सुझाव दिया गया था।

समूह 4 – एच.आई.वी. और टी.बी. सह–संक्रमण

समूह 4 ने सफलता की कहानियों का प्रचार करने के लिए डिजिटल मीडिया और लोकप्रिय रेडियो धारावाहिक – प्रधान मंत्री जी द्वारा मन की बात में बाइट्स इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी। इसने संयुक्त संदेशों का प्रचार करने का सुझाव भी दिया था, उदाहरणार्थ सह–संक्रमण, सेवा प्रदायगी आदि के संबंध में।

आगे का मार्ग - दर्शन

1. दो–दिवसीय कार्यशाला में संपन्न किए गए सामूहिक कार्य के फलस्वरूप आगे नए नवप्रवर्तनकारी संदेशों और संकल्पनाओं के साथ आधार सेवा गतिविधियों के लिए आई.ई.सी. सामग्री तैयार की जा सकेगी।
2. समूहों की सिफारिशों के अनुसार मौजूदा सामग्री में अंतरालों और चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा।
3. मौजूदा/नवप्रवर्तनकारी प्रोटोटाइप के मानकीकरण हेतु संवाद कार्यनीति तैयार की जाएगी और विषयवस्तु भी तैयार की जाएगी।
4. लक्षित समूहों के प्रतिनिधि समीक्षा हेतु प्रारूप सामग्रियों का अभिनिर्धारण करेंगे और तैयार की जाने वाली सामग्रियों में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुझावों/सिफारिशों/संशोधनों का संकलन करेंगे।
5. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या तैयार की गई सामग्रियां समाज में लोकार्पित किए जाने से पहले संभावित समूहों द्वारा स्वीकार्य और प्रभावकारी हैं, तैयार की गई सामगियों का पहले परीक्षण करने का सुझाव दिया गया था।

सुश्री नेहा पाण्डेय
आई.ई.सी. एंड एम.एस., नाको
श्री राजीव सिंधू,
बी.एस.डी., नाको

महाराष्ट्र में अनाथ और सुग्राही बच्चों के कल्याण हेतु सी.एस.आर. गतिविधियों के साथ अगसक्रिय रूप से प्रणबद्ध होने के लिए कार्यशाला में प्रतिनिधिगण

अनाथ और सुग्राही बच्चों (ओ.वी.सी.) की आवश्यकताओं के लिए प्रत्युत्तर अनुक्रिया को बढ़ाना तथा तेज करना – सी.एस.आर. परामर्श कार्यशाला

14 जुलाई 2017 को मुंबई में कर्नाटक हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट (के.एच.पी.टी.) ने यू.एस.एड की सहायता के साथ महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एम.एस.ए.सी.एस.), मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स नियंत्रण सोसायटी (एम.डी.ए.सी.एस.) और अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (एमेचैम्ब) के सहयोग से पूरे महाराष्ट्र में अनाथ और सुग्राही बच्चों, विशेषकर एड्स से प्रभावित बच्चों के कल्याण हेतु सी.एस.आर. गतिविधियों के साथ अग्रसक्रिय रूप से प्रणबद्ध होने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला के उद्देश्य

- सी.ए.बी.ए./ओ.वी.सी. की आवश्यकताओं को निवारण करने वाले सर्वांगीण मॉडल तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की साझेदारी करना और विशेषज्ञता का परस्पर लाभ उठाना।
- सी.एस.आर. और सरकारी निकायों के लिए एक ऐसी विधि से सहयोग करने के लिए, जो ज्ञान और क्रियान्वयन स्तर के बीच अंतराल को मिटाये और भागीदारियां, पक्षसमर्थन विकसित करके ओ.वी.सी. को मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखे और एक–दूसरे से सीखने का अवसरों का सृजन करे, एक मंच का सृजन करना।
- ओ.वी.सी. के जीवन चक्र के दौरान उनकी आवश्यकताओं का निवारण करने और बच्चे के समग्र कल्याण के लिए एक सहायक पारिवारिक पारिस्थितिकीतंत्र का निर्माण करना।

इस कार्यशाला में बच्चों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्यों और परियोजना के अनुभवों की साझेदारी करने पर फोकस किया गया। प्रतिभागियों द्वारा सी.ए.बी.ए./ओ.वी.सी. के जीवन चक्र के दौरान उनकी आवश्यकताओं जिनमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आर्थिक सहायता, कौशल विकास/व्यावसायिक सहायता शामिल हैं, और महिलाओं के सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन पहलकदमियों के माध्यम से एक बच्चे के समग्र कल्याण हेतु सहायक पारिवारिक परिस्थितिकीतंत्र का निर्माण करने पर बल दिया गया।

महारष्ट्र एस.ए.सी.एस. और मुंबई डी.ए.सी.एस. ने मौजूदा साक्ष्यों और ओ.वी.सी. की चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया, जिसके बाद बच्चों के साथ कार्य करने के उनके मॉडलों और अनुभवों के बारे में सी.एस.आर. प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार, एम.डी.ए.सी.एस., एम.एस.ए.सी.एस. और उनके भागीदारों, यू.एस.एड, सी.आई.आई. से गणमान्य व्यक्तिगण, कंपनियों और के.एच.पी.टी. से सी.एस.आर. लीडर्स उपस्थित थे।

ओ.वी.सी. के संबंध में कार्यशाला में प्रतिभागी

इस परामर्श से उपयोगी योजना बनाने, संसाधनों के यथेष्ट आबंटन और उपयुक्त क्रियान्वयन के लिए कारपोरेट क्षेत्र और सरकारी निकायों के बीच समन्वित प्रयास प्रारंभ करने और उनमें तेजी लाने में सहायता मिलेगी। सी.ए.बी.ए./ओ.वी.सी. के लिए महत्त्व वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और पोषण का निवारण करने हेतु एक सी.एस.आर. पहल है। इस कार्यशाला ने विभिन्न कारपोरेट सी.एस.आर. पहलों के बीच सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का सार निकालने के लिए भी अवसरों का सृजन किया जिनमें सुग्राही बच्चों को शामिल करते हुए दृश्यता और परस्पर विद्याप्राप्ति के लिए एक संकलित प्रकाशन तैयार करना शामिल था।

आगे का मार्ग - दर्शन

अगलाकदम एक सहायता संघ बनाना होगा जहाँ बच्चों के मसलों को सामूहिक रूप से हल करने के लिए विशेषज्ञता के निर्दिष्ट क्षेत्रों, ज्ञान और निधियों के साथ सी.एस.आर. एक साथ आएंगे।

श्री रवि भूषण
परामर्शदाता आई.ई.सी. एंड एम.एस. नाको

लाइफ–कलस्टर गतिविधियों के लिए प्रयोगाशालाएं

24 जुलाई को मुंबई में केन्द्रक अधिकारी संवेदीकरण बैठक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यू.एस. सेन्टर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सी.डी.सी.) की सहायता के साथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विशेष जिलों में ए.टी.आर. केन्द्रों के साथ सह–स्थित 22 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव कर रहा है। क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लैब्स फॉर लाइफ (एल4एल) परियोजना के माध्यम से इस पहलकदमी का क्रियान्वयन करने वाला भागीदार है।

उद्देश्य:

1. ए.आर.टी.–पूर्व और ए.आर.टी.–पर मरीजों और मुफ्त नैदानिक सेवाएं पहल के लिए नाको के प्रचालनिक दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित जांचों में सहायता करने के लिए अंतरालों को खत्म करना।
2. ए.आर.टी. केन्द्रों के साथ सह–स्थित चुनिंदा जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करना।
3. ए.आर.टी. केन्द्रों और सामान्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के बीच लिंकेज स्थापित करना।
4. अवसरवादी संक्रमणों (ओ.आई.) का पता लगाने के लिए तंत्र विकसित करना।

परियोजना के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ (2017–2019)

- गतिविधि 1: परिस्थिति विश्लेषण और अंतराल मूल्यांकन
- गतिविधि 2: क्षमता निर्माण गतिविधियां
- गतिविधि 3: गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां क्रियान्वित करना
- गतिविधि 4: संवेदीकरण, पक्षसमर्थन और संसाधन जुटाने के माध्यम से अवसंरचना अंतरालों का निवारण
- गतिविधि 5: ए.आर.टी., आई.सी.टी.सी. और अन्य प्रयोगशालाओं के बीच लिंकेज विकसित करना
- गतिविधि 6: कलस्टर गतिविधियों की आवधिक समीक्षाएं

इस परियोजना के पहले कदम के रूप में, सभी 22 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में एन.एच.एम. की एन.क्यू.ए.एस. जांच–सूची नं. 13 इस्तेमाल करते हुए बेसलाइन मूल्यांकन किया गया, जो एच.आई.वी./एड्स प्रयोगशाला सेवाओं की गुणवत्ता और रेफरल लिंकेज स्थापित करने के संबंध में योजना बनाने, समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी गतिविधियों के लिए अनिवार्य है।

मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

A. समग्र संस्थान स्कोर – महाराष्ट्र

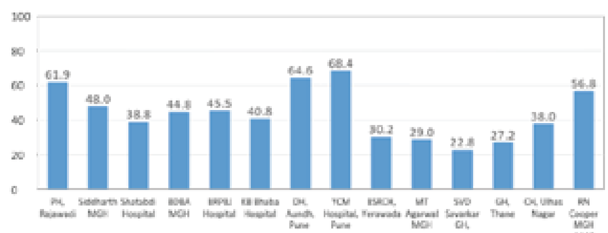

B. समग्र संस्थान स्कोर – आंध्र प्रदेश

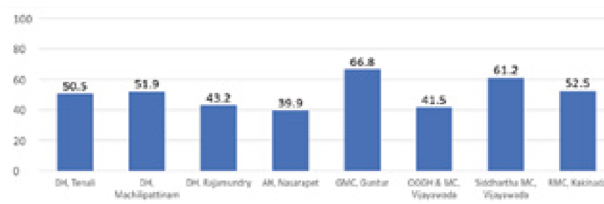

2–4 अगस्त 2017 को महाराष्ट्र के जिलों और 8–10 अगस्त 2017 को आंध्र प्रदेश के जिलों के लिए नमूना संग्रहण संबंधी प्रशिक्षण और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के पूर्व–विश्लेषण का आयोजन किया गया। अब बेसलाइन मूल्यांकन निष्कर्षों का प्रचार करने के लिए बैठकों की योजना बनाई जा रही है। बहुल हितधारकों के साथ यह नवप्रवर्तनकारी परियोजना आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कलस्टरों में 22 अभिनिर्धारित प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करने का इरादा रखती है। इसके अलावा, यह समयानुवर्ती संक्रमणों की पहचान करने के तंत्र प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार, यह परियोजना चुनिंदा प्रयोगशालाओं को नाको की प्रचालनिक दिशानिर्देश अपेक्षाओं को पूरा करने और ए.आर.टी. से पहले एवं के दौरान पी.एल.एच.आई.वी. को प्रयोगशाला सहायता उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएगी।

डॉ. अनु जॉर्ज
और टीम लैब्स फॉर लाइफ प्रोजेक्ट

'ब्राउन बैग' सेमिनार – वार्ता माला

'ब्राउन बैग' सेमिनार के दौरान वक्ता के रूप में डॉ. बिलाली कमारा

क्रॉस–सांस्थानिक सहयोग और क्षमता निर्माण की भावना के अनुसरण में, 'ब्राउन बैग' सेमिनार के तहत तीन वार्ताओं का आयोजन किया गया। जुलाई माह में डॉ. स्वरूप सरकार, निदेशक, संक्रामक रोग विभाग (सी.डी.एस.), डब्ल्यू.एच.ओ. एस.ई.ए.आर.ओ. द्वारा "एच.आई.वी. प्रत्युत्तर में वैश्विक नेतृत्व के पथ पर वापस आना" और अगस्त माह में डॉ. बिलाली कमारा, भारत के लिए यू.एन.एड्स कंट्री डायरेक्टर द्वारा 'भारत में एच.आई.वी./एड्सः शेष 50% को कैसे हासिल किया जाए?' पर फोकस किया गया। सेमिनार का लक्ष्य नाको, समुदाय, विकास भागीदारों और मुख्य हितधारकों में परियोजना प्रबंधकों की क्षमताओं एवं ज्ञान का निर्माण करना है। यह सेमिनार ज्ञान की साझेदारी, खुली वार्ता, नई प्रगतियों एवं परियोजना प्रबंधन के संबंध में परस्पर विद्याप्राप्ति के लिए प्रवेशद्वार के रूप में सेवा प्रदान करती है। डॉ. सरकार द्वारा वार्ता में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि चूँकि महामारी का परिदृश्य बदल रहा है और दाता वित्तपोषण घट रहा है, इसलिए ऐसी कार्यनीतियों का चिंतन करना जरूरी है जिनके द्वारा भारत 2030 एड्स तक समाप्त करने की दिशा में एच.आई.वी. के लिए वैश्विक प्रत्युत्तर में नेतृत्व प्रदान करना जारी रख सके।

डॉ. बिलाली कमारा ने उन प्रयासों पर चर्चा की जो 2030 की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में किए जाने की जरूरत है। भारत ने एच.आई.वी. महामारी को पराजित और नियंत्रित करने, तथा मानवाधिकारों, देखभाल एवं उपचार और कार्यनीतिक सूचना का संरक्षण करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले दशक में एच.आई.वी. संक्रमण की व्याप्ति लगभग आधी रह गई है और भारत में एड्स से जुड़ी मौतों में काफी कमी आई है। वक्ता ने मौजूदा जानपदिक रोग विज्ञान परिस्थिति का विश्लेषण किया और परिस्थिति को बदलने वाले उन कारकों पर चिंतन किया जो राष्ट्रीय एड्स परियोजना की पूर्ण क्षमता को उन्मुक्त कर सकते हैं और 2020 तक देश से 90:90:90 लक्ष्य और माँ से बच्चे को संचारण का उन्मूलन हासिल करवा सकती हैं।

सुश्री विनिता वर्मा
परामर्शदाता (मूल्यांकन एवं ओ.आर.), अनुसंधान, नाको

नाको एड्स एप

आज हम नए डिजिटल की दुनिया में रह रहे हैं, एक क्लिक हम पर किसी भी विषय के बारे में सूचना की बमबारी कर देती है। डिजिटल उपकरण बड़ी आसानी से पूरी दुनिया में लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसी तर्ज पर, नाको ने एक एंड्रॉयड मोबाइल एप "नाको एड्स एप" विकसित किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस एप का लोकार्पण किया गया और नेशनल हेल्थ पोर्टल (एन.एच.पी.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर होस्ट किया गया। अभी यह एप केवल एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और अंग्रेजी एवं हिंदी में उपलब्ध है। इस एप का लक्ष्य जागरुकता पैदा करना और एच.आई.वी./एड्स के संबंध में अंतिम उपयोगकर्ताओं को सार्थक सूचना उपलब्ध कराना है। एप की कुछ मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

एच.आई.वी. जोखिम मूल्यांकनः एक व्यक्ति को एच.आई.वी. होने के जोखिम के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक संवादात्मक जोखिम मूल्यांकन टूल।

सुविधाएं खोजेंः नजदीकी सेवाओं जैसे ए.आर.टी. केन्द्र, आई.सी.टी.सी., एस.टी.आई. क्लनिक, ब्लड बैंक और ओ.एस.टी. केन्द्र का पता लगाने का टूल।

मिथक और तथ्यः यह सूचना उन संदेहों और मिथकों को स्पष्ट करने में सहायक है जो लोगों के मन में एच.आई.वी. के बारे में हो सकते हैं।

अन्य विशेषताओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.), सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर, वीडियो स्पॉट्स आदि शामिल हैं।

यह एप "NACO AIDS App" के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और https://play.google.com/store/apps/-details?id=com.naco.nhp पर विजिट किया जा सकता है।

उपयोगकर्ताओं द्वारा कुछ समीक्षाएं इस प्रकार हैं:

गजूला महेन्द्र: *"सभी लोगों, परामर्शदाताओं तक के लिए अत्यधिक सूचनाप्रद और उपयोगी और पी.एल.एच.आई.वी. को भी एप के जरिये लाभ होता है।"*

डी.ए.पी.सी.यू. विजयनगरम: *"यह एच.आई.वी./एड्स के खिलाफ लड़ाई में न केवल मरीजों के लिए, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है।"*

कुवेथिलू राखो: *"यह बहुत मददगार है क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ।"*

आगे के मार्ग के रूप में, यह परियोजना अपडेट्स और नाको एड्स को कस्टमाइज करने और सुविधाओं पर नियमित रूप से निगरानी रखने पर फोकस कर रही है। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर सफलता के बाद, इस एप को iOS प्लेटफॉर्म पर लोकार्पण करने पर विचार किया जा रहा है। समुदायों और आम जनता द्वारा यह एप डाउनलोड किए जाने का और एक क्लिक पर एच.आई.वी./एड्स के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाने का नाको पक्षसमर्थन करता है।

सुश्री निधि रावत और सुश्री पीयूषी कोठीवाल
परामर्शदाता (आई.ई.सी. डिवीजन), नाको

मेट्रो ब्लड बैंक परियोजना का शुभारंभः कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आधुनिकतम रक्ताधान सेवाएं

श्री आर.के. वत्स, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार श्री अनिल वर्मा, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, पश्चिम बंगाल सरकार और श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको के साथ

10 जुलाई 2017 को श्री अनिल वर्मा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, पश्चिम बंगाल सरकार और श्री आर.के. वत्स, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पश्चिम बंगाल की भूमि पर, जो राज्य द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, केन्द्र की स्थापना और संचालन के लिए केन्द्र सरकार की सहायता को औपचारिक रूप प्रदान किया।

श्री जॉली जे लाजारूस,
परियोजना अधिकारी (वी.बी.डी.), नाको

राज्य

मुंबई

पी.एल.एच.आई.वी./सी.एल.एच.आई.वी. के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के उद्ग्रहण के संबंध में राज्य स्तरीय परामर्श – बालसंगोपन और संजय गांधी योजना

मुंबई में राज्य स्तरीय परामर्श बैठक में प्रतिनिधिगण

27 जुलाई को मुंबई जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा के.एच.पी.टी. की सहायता के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग और संजय गांधी योजना के साथ एक राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस परामर्श बैठक का उद्देश्य बालसंगोपन और संजय गांधी योजना का लाभ उठाने में एच.आई.वी./एड्स के साथ जीवन बिताने वाले लोगों एवं बच्चों के सामने वाली चुनौतियों का पता लगाना और उन पर काबू पाना था। इस बैठक में श्री परिमल सिंह, आई.ए.एस, परियोजना निदेशक, एम.एस.ए.सी.एस. श्रीमती प्रशिला जाधव दिवाकर, डिप्टी कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय डॉ. पदमजा केसकर, परियोजना निदेशक, एम.डी.ए.सी.एस. डॉ. श्रीकला आर्चाय, ए.पी.डी., एम.डी.ए.सी.एस. श्री फदौल, जिला डब्ल्यू.सी.डी. अधिकारी, ठाणे; श्री पाटनकर, जिला डब्ल्यू.सी.डी. अधिकारी, मुंबई उपनगरीय भी उपस्थित थे। श्री अशीष वर्मा, परियोजना अधिकारी, नाको ने परस्पर विद्याप्राप्ति के रूप में अन्य राज्यों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अपनाए जाने पर बल दिया। श्रीमती प्रशिला जाधव दिवाकर, डिप्टी कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय ने एस.जी.वाई. योजनाओं के बारे में बताया और श्री पाटनकर, डी.डब्ल्यू.सी.डी. अधिकारी ने बालसंगोपन योजना पर फोकस किया। एच.आई.वी. और एस.एल.एन. के साथ जीवन बिताने वाले बच्चों द्वारा "समुदाय से आवाज" एक आंख खोलने वाली बात थी।

बैठक के परिणाम:

- डिप्टी क्लेक्टर, मुंबई ने आश्वस्त किया कि जरूरतमंद लोगों को 21,000/– प्रति वर्ष की आय की स्वघोषणा दी जाएगी।
- ट्रांसजेन्डर उपयुक्त पद्धति के माध्यम से अपने नाम बदल सकते हैं और आवेदन के साथ राजपत्र की प्रति जमा करवा सकते हैं।
- सुग्राहिता के मसले के संबंध में तलाथी का संवेदीकरण किए जाने की आवश्यकता है। एम.डी.ए.सी.एस. संवेदीकरण कार्यशाला प्रारंभ कर सकती है।
- एम.डी.ए.सी.एस. जरूरतमंद लोगों की सूची तैयार करेगी और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करेगी।
- बालसंगोपन के अंतर्गत लाभों को उपलब्ध कराते समय इस मसले को सुलझाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सुश्री दयानेश्वरी सोनावने
उप निदेशक (एम.एस.), एम.डी.ए.सी.एस.

पश्चिम बंगाल

नवजात/बच्चों की एच.आई.वी. जांच

हाल ही में, पश्चिम बंगाल ने एन.एन.सी.यू. (रुग्ण नवजात देखभाल एकक) और एन.आर.सी. (पोषण स्वास्थ्य लाभ केन्द्र) में दाखिल नवजातों/बच्चों की चार लक्षणी रोग–नैदानिक जांचों, अर्थात अपरिपक्वता, मुखी छाला, निमोनिया और पूतिता के बाद एच.आई.वी. जांच प्रारंभ की है। आई.सी.टी.सी. द्वारा वस्तुस्थिति की पुष्टि किए जाने के बाद प्रतिक्रियाशील बच्चों के अभिभावकों को सूचित किया जाता है।

सभी जिलों में जांच के संबंध में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। कुल, 16 रोगसूचक बच्चों की एस.एन.सी.यू. में और 7 की एन.आर.सी में एच.आई.वी. के लिए जांच की गई।

सुश्री सुमिता सामंत
उप निदेशक (मेनस्ट्रीमिंग) डब्ल्यू.बी.एस.ए.पी. एवं सी.एस.

स्वच्छता पखवाड़ा – एक परिसर स्वच्छता अभियान

स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर पश्चिम बंगाल सूचनापत्र का विमोचन

पश्चिम बंगाल एड्स नियंत्रण सोसायटी (डब्ल्यू.बी.ए.सी.एस.) के सहयोग से पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) सेल ने एक पखवाड़े के लिए, अर्थात 1 – 15 अगस्त 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा, एक परिसर स्वच्छता अभियान मनाया। यह युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय, भारत सरकार और उच्चतर शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार की एक पहल है। प्रोफेसर वसव चौधरी, उप–कुलपति, डब्ल्यू.बी.एस.यू. ने मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य किया। सुश्री पियाली दास, सहायक निदेशक, डब्ल्यू.बी.एस.ए.सी.एस. ने एच.आई.वी./एड्स के संबंध में सत्र का संचालन किया और छात्र–छात्राओं के साथ संवाद भी किया।

सुश्री पियाली दास
सहायक निदेशक (युवा कार्य) डब्ल्यू.बी.एस.ए.पी. एवं सी.एस.

कर्नाटक

सी.एल.एच.आई.वी. के लिए पोषण परियोजना

निदेशक, ओ.डी.पी. द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण

ऑरग्नाइजेशन फॉर द डेवलेपमेंट ऑफ पीपल (ओ.डी.पी.) स्नेहाश्रय समिति कोडागू, स्वसहायता समूह के साथ कार्यरत एक गैर–सरकारी संगठन ने ओ.डी.पी. कर्मचारियों, आयुक्त – स्काउट एवं गाइड्स, लॉयनेस क्लब मेडेकेरी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलोदय महिला ओक्कुटा, स्वसहायता समूह सदस्यों, डी.ए.सी.ओ., डी.आई.एस., पी.एल.एच.ए. और अन्य के समन्वय के साथ क्लिंटन फाउंडेशन की सहायता के साथ कोडागू जिले में एच.आई.वी. पॉजीटिव बच्चों को मासिक आधार पर पोषण सहायता (अनाज, दालें, तेल आदि) मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

- बच्चों की संख्या जिन्हें पोषण सहायता मुहैया कराई गई — **28**
- बच्चों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति मुहैया कराई गई — **18**
- बच्चों की संख्या जिन्हें स्वेटर, छाता, नोटबुक मुहैया कराई गई — **24**
- बच्चों की संख्या जिन्हें आवास सहायता उपलब्ध कराई गई — **1**

श्री गोविन्दराजू टी.
उप निदेशक (मेनस्ट्रीमिंग एवं सामाजिक सुरक्षा)
कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसायटी

तेलंगाना

एच.आई.वी./एड्स को मुख्य धारा में लाने के संबंध में अंतर–विभागीय बैठक

अंतर–विभागीय बैठक के दौरान सदस्यों के बीच विचार–विमर्श

4 अगस्त 2017 को तेलंगाना सरकार के विभागों के साथ एच.आई.वी./एड्स को मुख्य धारा में लाने के संबंध में राज्य स्तरीय अंतर–विभागीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना विभाग, शिक्षा विभाग, युवा प्रगति विभाग, एलायंस इंडिया, विहान, साथी और पॉजीटिव नेटवर्कों ने भाग लिया।

विशिष्टताएं

- उन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया जहां एच.आई.वी./एड्स के मसलों का निवारण करने के लिए विभागों द्वारा प्रयास अपेक्षित हैं।
- एच.आई.वी./एड्स के संबंध में केन्द्रक अधिकारियों का नामांकन और विभागों में एच.आई.वी./एड्स के संबंध में टी.ओ.टी. के पूल का सृजन करने के लिए प्रतिभागियों की सूची उपलब्ध कराना।
- लाइन विभागों के माध्यम से पी.एल.एच.आई.वी. और एम.ए.आर.पी. के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करने के लिए परिधि का अभिनिर्धारण किया।
- नाको द्वारा अनुमोदित मेनस्ट्रीमिंग वार्षिक कार्य योजना का विभागों के साथ क्रियान्वयन।
- किशोरावस्था शिक्षा परियोजना और लाल रिबन क्लब परियोजना के लिए कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन।
- कर्मचारियों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण।

श्री एस. श्रीकर
परामर्शदाता मेनस्ट्रीमिंग, टी.एस.ए.सी.एस.

छत्तीसगढ़

रक्तदान महाशिविर

शिविर में स्वैच्छिक रक्तदाता

8 अगस्त 2017 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.), जगदलपुर में एक रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान महाशिविर में जगदलपुर मेडिकल कालेज द्वारा लगभग 500 ब्लड बैगों का संग्रहण किया गया।

श्री अजय, क्षेत्रीय समन्वयक

एड्स को रोकने के लिए हाथ मिलाइये – एच.आई.वी./एड्स जागरुकता के लिए मानव श्रृंखला बनाना

4000 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई

एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरुकता फैलाने और सुग्राही समुदायों एवं एच.आई.वी. के साथ जीवन बिताने वाले लोगों द्वारा झेले जाने वाले कलंक को कम करने की दृष्टि से, 12 सितंबर 2017 को मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी (एम.पी.एस.ए.सी.एस.) ने "एड्स को रोकने के लिए हाथ मिलाइये" अभियान का आयोजन किया। इस जागरुकता अभियान की विशिष्टता विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेजों, लक्षित हस्तक्षेप, गैर–सरकारी संगठनों, लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसायटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पॉजीटिव नेटवर्कों आदि के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाना थी। भोपाल झील के तट पर, वी.आई.पी. रोड के रमणीय स्थल पर एक मानव श्रृंखला सफलतापूर्वक बनाई गई।

प्रतिभागियों को पर्चे और बैनर दिए गए, लाल रिबन के बोर्ड, पट्टियां और बड़े कट–आउट्स का भी प्रदर्शन किया गया था और लोक मंडलियों एवं जादूगरों ने विभिन्न आकर्षक करतबों का प्रदर्शन किया।

श्री रुस्तम सिंह, मानीय जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश सरकार प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

श्री रुस्तम सिंह, माननीय जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश सरकार ने इस अभियान को झंडी दिखाई और मानव श्रृंखला बनाए जाने का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के दौरान, श्री रुस्तम सिंह ने उल्लेख किया कि एम.पी.एस.ए.सी.एस. की कारगर कार्यनीतियों और प्रयासों के कारण एच.आई.वी. की संक्रमण दर में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि संक्रमणों को नियंत्रित करने में जागरुकता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और युवा वर्ग भी जागरुकता पैदा करने की गतिविधियों में सहायता कर सकता है। उन्होंने एम.पी.एस.ए.सी.एस. द्वारा किए गए प्रयास की प्रशंसा की और एम.पी.एस.ए.सी.एस. की टीम को निजी तौर पर बधाई दी।

एड्स/एच.आई.वी. के बारे में जादू प्रदर्शन

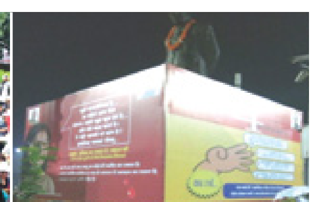
अभियान का पूर्व–प्रचार

इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति, जैसे डॉ. पल्लवी जैन गोविल, स्वास्थ्य आयुक्त, श्री उमेश कुमार, परियोजना निदेशक, एम.पी.एस.ए.सी.एस., श्री वीरेन्द्र मिश्रा, राष्ट्रीय निदेशक, आर.एस.एस. एवं आई.पी.एस., श्री राजीव वर्मा, डी.जी. पुलिस, डॉ. आर.के. विजय, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं निर्देश, एन.एस.एस., उच्चतर शिक्षा विभाग के उप सचिव एवं राज्य प्रमुख भी उपस्थित थे।

सुश्री सविता ठाकुर
एवं टीम एम.पी.एस.ए.सी.एस.,

समारोह

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस

वैश्विक समाज का संवर्धन करने में विश्व के युवाओं के प्रयासों का सम्मान करने के लिए, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनााया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2017 विवाद की रोकथाम एवं कायाकल्प और समावेशन, सामाजिक न्याय और दीर्घकालिक शांति के लिए युवा लोगों के अंशदान का उत्सव मनाने के प्रति समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय "शांति का निर्माण करते युवा" था।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों ने रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, लोककला प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों, चित्रकारी प्रतियोगिताओं, प्रसारित कार्यक्रमों और कालेजों में सूचनाप्रद सत्रों के रूप में पूरे राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। आइये, हम एक नजर डालें!

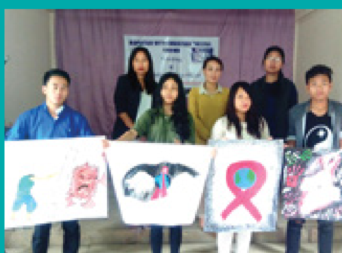
नागालैंड

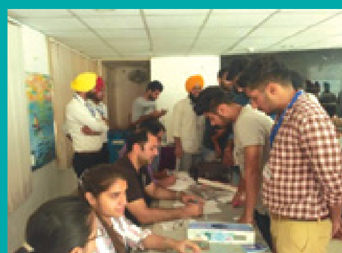
पंजाब

उत्तर प्रदेश

असम

छत्तीसगढ़

पश्चिम बंगाल

कर्नाटक

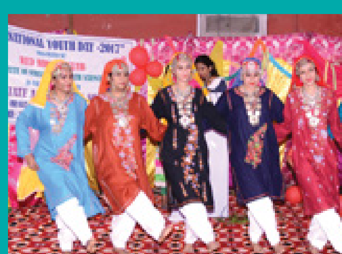
जम्मू और कश्मीर

मणिपुर

महाराष्ट्र

मुंबई में सी.एस.आई.बी.ई.आर. कालेज में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया और सुश्री हेमल इंगले, मिस इंडिया एक्सुसाइट क्वीन फॉर द कॉज 2016–17 और मिस अर्थ इंडिया फायर 2016 मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कोल्हापुर ज़िले के लिए एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के कुलीन निमित्त हेतु एक "अम्बेसडर" के रूप में कार्य करने की अपनी इच्छा जाहिर की और युवाओं से उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलने के लिए अपील भी की। श्री हितेश मनदोदी, राष्ट्रीय दौड़ चैम्पियन ने भी सिविल सर्जन, सी.पी.आर. अस्पताल, प्रमुख समाज कार्य विभाग और सी.एस.आई.बी.ई.आर. के कर्मचारियों एवं डी.ए.पी.सी.यू. टीम के साथ इस समारोह में भाग लिया। इस समारोह में 400 से अधिक कालेज छात्रों ने भाग लिया।

संरक्षक: श्री संजीव कुमार, अपर सचिव (स्वास्थ्य) एवं महानिदेशक, नाको, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

संयुक्त सचिव, नाको: श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको

संपादक: डॉ. नरेश गोयल, डी.डी.जी. (नाको)

संपादकीय पैनल: डॉ. आर.एस. गुप्ता (डी.डी.जी.), डॉ. एस. वेंकटेश (डी.डी.जी.), डॉ. के.एस. सचदेवा, (डी.डी.जी.), डॉ. शोभिनी राजन, (ए.डी.जी.), डॉ. राजेश राणा, (राष्ट्रीय परामर्शदाता), सुश्री नेहा पाण्डे, (परामर्शदाता), नाको

नाको समाचार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का सूचनापत्र है।

9वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली – 110001, दूरभाष: 011-23325343, फैक्स: 011-23731746, www.naco.gov.in

संपादन, डिज़ाइन और निर्माण: द विजुयल हाउस, ईमेल: tvh@thevisualhouse.in

मुफ्त एवं गुप्त परामर्श और जाँच के लिए सबसे नजदीकी सरकारी अस्पताल में एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) में पधारें

सरकारी अस्पतालों में एंटीरेट्रोवायरल थैरेपी सेन्टर मे एच.आई.वी. का मुफ्त इलाज उपलब्ध है